



::आयुक्त (अपील) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करबीरकेन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: commrappl3-cexamd@nic.in



सत्यमेव जयते

DIN20221164SX000001590A

क

अपील / फाइलसंख्या/
Appeal / File No.
GAPPL/COM/STP/1738/2022

मूल आदेश सं /
O.I.O. No.
08/SERVICE
TAX/DEMAND/2021-22

दिनांक/Date
30-Mar-22

2387 10 2242
05/12/2022

EG1245158914 IN
Party.

अपील आदेश संख्या(Order-in-Appeal No.):

BHV-EXCUS-000-APP-092-2022

आदेश का दिनांक /

Date of Order:
11.11.2022

जारी करने की तारीख /

Date of issue: 29.11.2022

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

ग

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधामा द्वारा
उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ

अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Ramdevsinh Agarsinh Jadeja, Hariom Nagar, Kallabid, Bhavnagar

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A)

सामान्य शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रांत अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i)

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, को जाननी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii)

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- 380016 को जाननी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaunali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, न्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

B)

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, न्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्वयं आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more Rs. 5 lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (iii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जमाना विवादित है, या जमाना, जब केवल जमाना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
 - (ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
 - (iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं- 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थीय स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा। /
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश को पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपर्याय के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जेवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of an excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो क्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं- 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तरीक अथवा समावाचिका पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संश्लेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O.I.O and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त वंग से किया जाना चाहिए। उक्त तथ्य के होते हुए भी की लिखा पत्र कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

:: अपील आदेश / ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Ramdevsinh Agarsinh Jadeja, Hariomnagar, Kaliyabid, Bhavnagar (hereinafter referred to as "Appellant") has filed the present appeal against Order-in-Original No. 8/Service Tax/Demand/2021-22 dated 30.03.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Superintendent, Range-2, CGST Division Bhavnagar-1 (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief, are that on the basis of departmental audit, proceedings were initiated against M/s. So Lucky Cable Service, Bhavnagar ("M/s. So Lucky") for evasion of service tax under the category of "Cable Operators Services". Proceedings were also initiated against sub-cable operator of M/s. So Lucky including the Appellant, for non-payment of service tax by wrongly claiming benefit of value-based exemption under Notification No. 06/2005-ST dated 01.03.2005, despite providing services under other's brand name. These proceedings resulted in issuance of SCNs to the various service providers including the Appellant. The jurisdictional authority issued another SCN No. EVN/ST/CTY/SCN-SOLUCKY/101/16-17 dated 25.10.2018, for the period from April-2016 to June-2017 to the Appellant, proposing demand of service tax amount of Rs. 1,09,800/- (including Education Cess and S.H. Education Cess) along with interest and for imposition of penalty under Sections 76 and 77 of the Finance Act, 1994("the Act").

3. The above Show Cause Notice was adjudicated vide impugned order wherein the adjudicating authority confirmed the demand of service tax amount of Rs. 1,09,800/- (including Education Cess and S.H. Education Cess) under Section 73 of the Act along with interest under Section 75 of the Act; imposed penalty of Rs. 10,000/- or Rs. 200/- for every day during which such failure continues whichever is higher starting with the first day after the due date, till the date of actual compliance under Section 77(2) of the Act for not filing ST-3 returns; imposed a penalty of Rs. 10,000/- under Section 77(1) (a) of the Act for not obtaining registration and imposed a penalty not less than Rs. 200/- per day or penalty not exceeding Service Tax amount under Section 76 of the Act;

4. Being aggrieved by the impugned order, the Appellant preferred present appeal contending, *inter-alia*, as under:

(i) The impugned order is not correct as it has been passed without making legal interpretation of provisions of the Act. The Appellant was providing the taxable services of "Cable Operator" to transmission of waiver through electronically system. The taxable value had not been exceeded more than Rs. Ten Lakh in any of the financial year for the period under:



reference. They had not provided the taxable service by using symbol of "So Lucky" cable. They are entitled to avail the benefit of Notification No. 06/2005-ST dated 01.03.2005 as they have not provided the taxable service using the brand name of So lucky cable and value of their service is less than threshold limit prescribed. The amount of Service Tax mentioned in the Order-In-Original is nothing but the taxable value mentioned in the business carried out by So lucky which is not in or in relation to the business carried out by them;

- (ii) In another similar type of case of Shri Chiragbhai Andhariya, the Commissioner (Appeals), Rajkot vide OIA No. BHV-EXCUS-000-019-2021-22 dated 01.04.2022 has clearly held that the Appellant is liable to avail the benefit of Notification No. 6/2005-ST dated 01.03.2005.
- (iii) They rely on case law as reported at 2009 (14) STR 511 (Trib.-Del.) and 2018 (18) GSTL 152 (AAR-GST).

4.1. The Appellant filed written submission vide letter dated 04.03.2022 wherein they *inter-alia* contended that

- a) The Appellant has not provided the taxable service as contemplated under the Act as they were not directly involved in transmission as the main service was provided by M/s. So Lucky using the electronic system installed by them;
- b) The reliance is again placed upon the Hon'ble Tribunal's order dated 02.11.2016 on similar issue.

5. The personal hearing in the matter was held on 20.10.2022 which was attended by Shri N. K. Maru & U. H. Qureshi, Consultants of the Appellant. During the personal hearing they reiterated the grounds of appeal.

5.1 I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the Appeal Memorandum and oral as well as written submission made by the Appellant. The issue to be decided in the present case is as to whether the impugned order confirming demand of Service Tax amounting to Rs. 1,09,800/- (including Education Cess and S.H. Education Cess) under Section 75 of the Act, along with interest and imposition of penalties under Section 76, 77(1)(a) and 77 of the Act is legally correct or otherwise.

6. I find that the adjudicating authority has confirmed the demand primarily on the ground that the Appellant as sub-cable operator has provided services under the Brand name of "M/s. So Lucky Cable Service" and hence value-based exemption under Notification No. 06/2005-ST dated 01.03.2005 as amended is not available to them.

Amal

6.1 I find that the then Commissioner (Appeals) vide a Order-In-Appeal No. 61 to 64/2013(BVR)SKS/Commr.(A)/Ahd dated 03.05.2013, in an identical issue, has dismissed the appeals filed by the department observing as under:-

"The contentions of the department is that the respondents had used the brand name of their respective MSO in transmitting the signals. In this regard I find that the signals which the respondent had re-transmitted were of different distributors which were transmitted by the respective MSO to them. I am of the considered opinion that these signals do not bear any brand name and style of the MSO. At the most it can be said that the signals are in the name and style of distributors of that film or programme. Therefore, contention of the department that the services provided by the respondents were with the brand name of their respective MSO is not acceptable. Therefore, appeals filed by the department for denying the benefit of the exemption under notification no. 6/2005-ST dated 01.03.2005 as amended and for imposing penalty under Section 76,77 & and 78 of the Finance Act, 1994 does not succeed.

Thus, the Commissioner (Appeals), vide above Order-In-Appeal has categorically held that the respondent sub-cable operator, was eligible for value-based exemption under Notification No. 6/2005-ST dated 01.03.2005, as amended by Notification No. 33/2012-S.T. dated 20.06.2012. The appeals filed by the revenue against above Order-In-Appeal have been dismissed by the Hon'ble Tribunal vide Order No. A/11410-11506/2016 dated 02.11.2016 considering the low revenue involved therein.

6.2 I also find that the then Commissioner (Appeals) vide Order-In-Original No. BHV-EXCUS-APP-000-019-2021-22 dated 01.04.2022 has already decided the matter in favour of Shri Chirag Harendrabhai Andhariya for the period April-2011 to March-2015, by allowing the benefit of Notification No. 06/2015-S.T. dated 01.03.2005, as amended. Accordingly, following the findings recorded in Order-In-Appeal dated 03.05.2013 as well as Order-In-Appeal dated 01.04.2022, I hold that services provided by the Appellant cannot be considered as provided under other's brand name, and hence, the benefit of value based exemption under Notification No. 6/2005-ST dated 01.03.2005, as amended vide Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012, is available to the Appellant.

7. In view of above discussions and findings, I allow the benefit of threshold limit as prescribed under Notification No. 6/2005-Service Tax dated 01.03.2005 as amended vide Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012, to the Appellant subject to the conditions prescribed therein.

8. I direct the Adjudicating Authority to calculate and convey the Service

Asy
11-11-2022

Tax liability of Appellant after allowing benefit of the Notification as mentioned in Para 7 supra within 30 days of receipt of this order. I also direct the Adjudicating Authority to keep in mind the provisions of Para 3(iii) of the Notification No. 33/2012-Service Tax dated 20.06.2012 while calculating the Service Tax liability of the Appellant.

9. Further, I uphold the interest on Service Tax if any, as discussed in para 7 & 8 above. I also uphold penalties under Section 76, Section 77(2), and Section 77(1)(a) of the Act on the Appellant in case the taxable value is more than threshold limit.

10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.


(शिव प्रताप सिंह)/(Shiv Pratap Singh),
आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s. Ramdevsinh Agarsinh Jadeja, Hariomnagar, Kaliyabid, Bhavnagar	सेवा में, मे. रामदेवसिंह अगरसिंह जाडेजा, हरीओम नगर, कालियाबिड, भावनगर।
--	--

प्रतिलिपि :-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर आयुक्तालय, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर मण्डल-1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5) अधीक्षक, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-2, भावनगर मण्डल-1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6) गार्ड फाइल।